आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72(क) के अधीन कर के लाभ दिये जाते हैं ।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्निर्माण से प्रभावित कामगारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करेगा ।

(7) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुनः-स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया है ।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रु० तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है ।

(9) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रूग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रही है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000 रुपये तक की जाती है ।

(10) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है ।

**Disproportionate increase in employment of SSIs**

@3020 SHRI RAM JETHMALANI:

DR. JINENDRA KUMAR JAIN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the constant increase in the number of Units of small scale industries during the last several years in the country, the number of workers employed therein is not increasing;

(b) if so, whether it is also a fact that despite an increase of 6.8 percent in the number of small scale units in 1991-92 as compared to that of in the year 1990-91, the number of workers employed therein has registerrd an increase of only 3 percent; and

(c) if so, whether Government propose to urge upon the respective Departments to take effective steps for encouraging the establishment of labour intensive industries in the country in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir. Along with growth in number of units there has also been growth in the number of workers employed.

(b) Yes, Sir.

(c) Promotion of small scale industries is a State subject. State|UT Goverments have their own programmes for the development of small scale units. Particularly labour intensive small scale units. The Government of India also provides various types of concessions and incentives for encouraging establishment of small scale units.

@Previously Unstarred Question 2413, transferred from 15th March, 1993.